



बर्ड ऑफ पैरडाइज समूह की एक प्रजाति "क्रिकल कॉलर्ड मैनुकोड" न्यू गिनी और वैंस्ट पापुआ के मिसूल द्वीप के पहाड़ी और मैदानी भागों के जंगलों में मिलती है। इस प्रजाति के पक्षियों का प्रमुख भोजन फल और अंजीर है। अपने प्राकृतिक आवास में दूर-दूर तक फैले और बड़ी संख्या में नजर आने वाले इन पक्षियों को इंटरनेशनल यूनिवर्सल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन) की रेड लिस्ट में "लीस्ट कन्सर्न" (कम चिंताजनक) वर्ग में रखा गया है तथा ये, जानवरों के अवैध व्यापार को लेकर हुई संधि, सी.आई.टी.ई.एस. में भी अधिसूचित हैं। मध्यम आकार के ये पक्षी 36 सेंटीमीटर तक लम्बे होते हैं। नीली-हरी तथा काली व बैंगनी आभा वाले इन पक्षियों की मुख्य पहचान है, लम्बी पूंछ और आँखों की सुर्ख लाल पुतलियाँ। इनकी छाती के पंख चमकदार हरे रंग के होते हैं। सबसे खास बात यह है कि, नर और मादा लगभग एक जैसे दिखते हैं, बस मादा थोड़ी छोटी होती है और उसका बैंगनी रंग कुछ हल्का होता है। यह प्रजाति देखने में जोबी मैनुकोड जैसी लगती है। लेकिन क्रिकल कॉलर्ड मैनुकोड चिड़ियाँ मूलतः ऊंचे भागों में मिलती हैं और इनके सिर पर एक खास तरह का उभार होता है।

'पार्टी विधानसभा चुनाव गहलोत के चेहरे, बैनर व नेतृत्व में नहीं लड़ेगी'

कांग्रेस की भारी-भरकम मीटिंग, जिसमें खड़गे, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठतम नेता भी मौजूद थे, में यह स्पष्ट निर्णय हुआ

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। राजस्थान विधानसभा के आगामी चुनाव में कांग्रेस का "चीफ मिनिसटर का कोई चेहरा नहीं होगा।"

पार्टी अशोक गहलोत के चेहरे, बैनर या नेतृत्व के तले चुनाव नहीं लड़ेगी, हालांकि वे मुख्यमंत्री हैं।

यह अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा झटका है, जो खुद को पार्टी के लिए एक मात्र विकल्प बता चुके हैं।

सचिन पायलट की भावी भूमिका के बारे में भी पार्टी के इस सैकशन ने कोई जवाब नहीं दिया जो मीडिया के सम्पर्क में है। सवाल है कि क्या सचिन को ए.आई.सी.सी. महासचिव के रूप में नई दिल्ली लाया जा रहा है।

सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कि वे राजस्थान में अपनी जगह छोड़कर दिल्ली क्यों आएंगे। ये प्रस्ताव तो गत दो साल से आ रहे हैं और वे दिल्ली आने से लगातार इन्कार कर रहे हैं। ए.आई.सी.सी. सूत्रों ने कहा कि

पर, बैठक में सचिन पायलट की भूमिका के बारे में भी कोई स्पष्ट सोच सामने नहीं आया, हालांकि खड़गे ने गहलोत पर, जो जूम से बैठक में भाग ले रहे थे, कटाक्ष जरूर किया, "गहलोत जी, पट्टियां उतारिये तथा चुनाव अभियान में उतरिये।"

राहुल गांधी ने भी गहलोत सरकार के कामकाज के प्रति, "नाराजगी" दिखायी और कहा कि, सरकार अच्छी स्कीम लायी है, पर, अफसर सरकार चला रहे हैं, जबकि, सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिये और उनकी सरकार में चलनी चाहिये। राहुल ने इसी लय में यह भी कहा कि, कांग्रेस तैलंगाना, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जीत रही है, पर राजस्थान में कई मुद्दे हैं, जिन पर चिंता है।

हालांकि बैठक में यह भी कहा गया कि, पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में "जिताऊ" होना मुख्य मापदण्ड होगा, पर वर्तमान विधायकों के खिलाफ "भारी एन्टीइकम्बेंसी" है, क्योंकि गहलोत ने विधायकों की वफादारी जीतने के लिये उन्हें खुली छूट दे रखी थी।

इस स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि, कांग्रेस कम से कम 80 वर्तमान विधायकों के टिकट काटेगी।

सचिन पायलट को क्या भूमिका दी जाएगी, इस पर अभी भी विस्तृत चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि अभी उनका फोकस नेतृत्व द्वारा उनकी तीन मांगों को स्वीकार करवाए जाने पर है। समझा जाता है कि चुनाव तैयारी

में उनकी भूमिका पर चर्चा शुरू हो गई है।

लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उन्हें जो भी पद दिया जाएगा उससे गहलोत व उनके बीच संतुलन आएगा। उससे अशोक गहलोत और उनके बीच

संतुलन आएगा साथ ही टिकट वितरण से भी उन्हें तबज्जो मिलेगी।

इसके लिए उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा जैसा, छत्तीसगढ़ में किया गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने भाजपा मंत्रियों व नेताओं से मुलाकात का दूसरा दौर पूरा किया

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से मंत्रिमण्डल व संगठन में चुनाव पर चर्चा हुई

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने निवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक और बैठक की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष शामिल हुए। ये बैठक 28 जून से लगातार हो रही है। हालांकि इस बैठक का उद्देश्य

यह फेरबदल इस सप्ताह के अंत तक पूरे हो जाने थे, पर, महाराष्ट्र में अजीत पवार व उनके साथियों की शरद पवार के खिलाफ बगावत व एन.डी.ए. सरकार में शामिल होने से मचे हड़कम्प के कारण थम गये थे।

निर्मला सीतारमन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन मेघवाल, भूपेन्द्र यादव, किरण रिजिजू, प्र.मंत्री मोदी से इस संदर्भ में मिले।

अर्जुन मेघवाल व भूपेन्द्र यादव को राजस्थान के मु. मंत्री के रूप में देखा जा सकता। पर, अभी भाजपा हाई कमान वसुंधरा राजे की भूमिका के बारे में निर्णय नहीं ले पायी है। उन्हें केन्द्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है, उनका दबाव अत्यन्त शिफ्ट करने के लिये।

एक ब्राह्मण नेता को भी केन्द्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का नाम सबसे आगे है। कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को भी मंत्री बनाने की काफी चर्चा है।

संबंध में थी। ये परिवर्तन इस सप्ताह पूरे होने वाले थे, मगर वे महाराष्ट्र के घटनाक्रम के कारण टल गए, जहाँ एन.सी.पी. नेता अजीत पवार ने गत रविवार शिव सेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो अपने चाचा शरद पवार को झटका दे दिया।

प्रधानमंत्री ने सोमवार शाम अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों के काम की समीक्षा की। लेकिन उन्होंने फेरबदल को टाल दिया ताकि पहले एन.सी.पी. का संकट निपट जाए।

दो दिन पहले ही भाजपा ने चार राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए, जिनमें तेलंगाना में केन्द्रीय राज्य मंत्री किशन रेड्डी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि छह और राज्यों के अध्यक्ष बदले जाएंगे- गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक।

ऐसी अटकलें हैं कि कई केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में जिम्मेदारी दी जा सकती है। आधा दर्जन मंत्रियों की 4 और 5 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गृह मंत्री की संसदीय समिति की बैठक से विपक्ष का वाक आउट

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 जुलाई। संसद का मानसून सत्र कितना तूफानी होगा, इसकी झलक कल उस समय मिल गई, जब विपक्षी सदस्य "पार्लियामेन्ट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम" की मीटिंग से उस समय वाक आउट कर गये, जब मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की उनकी मांग को पैनल चीफ ने अस्वीकार

विपक्ष ने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि पैनल प्रमुख ने, मणिपुर के हालात पर चर्चा करने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की।

कर दिया।

सूत्रों ने कहा कि, राज्यों में जेल-सुधार पर चर्चा करने के लिये बुलाई गई उस मीटिंग में, टी.एम.सी. के डैरेक ओ'ब्रायन, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तथा प्रदीप भट्टाचार्य ने पैनल चेयरमैन बृजलाल को अपने पत्र सौंपते हुये कहा कि इस कमेटी के सदस्यों के रूप में वे मणिपुर की स्थिति की अनदेखी नहीं कर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी एक दम चुप क्यों हो गयीं?

चुप्पी का एक कारण तो है, राष्ट्रीय नेता बनने की उनकी महत्वाकांक्षा को धक्का लगना, महाराष्ट्र के घटनाक्रम से

ममता बनर्जी ने शरद पवार को पूरा समर्थन दिया था, विपक्ष की एकता की मुहिम में, पर, महाराष्ट्र में शरद पवार को झटका लगने से वे चुप हो गयी हैं।

दूसरा कारण है, बंगाल में पंचायत व म्युनिसिपैलिटी के चुनाव। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिये भारी महत्व रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव व अधिपत्य बरकरार रखने के लिये।

2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार वामपंथियों को हराकर, बंगाल में सरकार बनायी थी, पर, विधानसभा में जीत की नींव रखी गयी थी। पंचायत व म्युनिसिपैलिटी चुनाव में, जहां ममता बनर्जी ने वामपंथियों को हराकर, पहली बार भारी जीत हासिल की थी।

कार्यकर्ता व कैंडर की वफादारी जीतने के लिये, ये पंचायत व म्युनिसिपैलिटी चुनाव में धन उपलब्ध कराते हैं, स्थानीय ठेकों व छोटे-मोटे टैंडर के काम से।

ममता बनर्जी 2011 में राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतकर सत्ता में आई थीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने नगर पालिकाओं और पंचायतों

पर वाम मोर्चे के गठबंधन से सत्ता छीनी थी। 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत एवं ग्रामीण चुनावों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने करतार पुरा नाले पर सरकार से शपथ पत्र मांगा

जयपुर, 6 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि करतारपुरा नाले से अतिक्रमण हटाने और उसके पुनरुद्धार को लेकर हर तीन महीने में शपथ पत्र पेश कर दिए जाए

हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया कि, हर तीन माह में शपथ पत्र पेश कर बताया जाए कि, नाले से अतिक्रमण हटाने व पुनरोद्धार के लिए क्या-क्या किया गया है।

कार्यों की जानकारी दे। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव व प्रवीर भटनगर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि यह मामला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं 82 वर्ष का हूँ या 92 का, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी भी "इफैक्टिव" हूँ'

शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार की, शरद पवार पर की गयी टिप्पणी कि, "आप 83 वर्ष के हैं, क्या कभी "स्टॉप" नहीं करेंगे", का सटीक जवाब दिया

डॉ. सतीश मिश्रा-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 जुलाई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के आजीवन अध्यक्ष शरद पवार, जो अब तक अपने भतीजे अजीत पवार की अपनी आयु पर की गयी टिप्पणी पर चुप थे, ने आज घोषणा की कि किसी की उम्र चाहे कुछ भी हो महत्वपूर्ण यह है कि उसका प्रभाव कितना है। "मैं चाहे 82 का होऊं चाहे 92 का, मैं आज भी प्रभावशाली हूँ।"

गुरुवार को पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद शरद पवार ने जोर देकर कहा, "मैं (एन.सी.पी.) का

अजीत पवार ने यह भी कहा कि, हर पार्टी में रिटायरमेंट एज" होती है, भाजपा में भी 75 वर्ष है। शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने भी जवाब में कहा, "अजीत भूल गये कि, भाजपा में "रिटायरमेंट एज" मंत्री के लिये है, राजनीतिक नेताओं के लिये नहीं। सुले ने यह भी कहा कि, जो सीनियर हो गये वे रिटायर हों, यह कोई स्थापित उसूल नहीं है। रतन टाटा 86 वर्ष के हैं, अभी कार्यरत हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के सायरस पूनावाला की उम्र 84 वर्ष है, अभी भी कार्यरत हैं। अमिताभ बच्चन 82 वर्ष के हैं और कार्यशील हैं। वॉरन बफैट व फारूख अब्दुल्ला का भी इस बारे में ज्वलन्त उदाहरण है। शरद पवार के दिल्ली निवास पर आयोजित एन.सी.पी. की कार्यकारिणी की बैठक में, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे व उन नौ अन्य नेताओं को पार्टी से निकालने के निर्णय की पुष्टि की गई, जिन्होंने एन.डी.ए. की सरकार से हाथ मिलाकर मंत्री पद संभाला।

अध्यक्ष हूँ।" बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य नौ के

निष्कासन को स्वीकृति दी गई जिन्होंने कल अजीत पवार ने अपने चाचा

के इस उम्र में प्रमुख राजनैतिक भूमिका निभाने पर प्रश्न उठाया था। उन्होंने

कहा, "अन्य पार्टियों में नेता एक उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं। भाजपा में नेता 75 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, आप कब होंगे। आपको दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमें बताइए। आपकी उम्र 82 साल है, आप रुकेंगे या नहीं। 63 वर्षीय अजीत यह भूल गए कि यह बात केवल मंत्रियों पर लागू होती है, पार्टी नेताओं पर नहीं। शरद पवार द्वारा आहूत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 12 विधायी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया, जिनमें उनका भतीजा अजीत और सबसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस का ए.टी.एम.'

जाल खंबाता-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 जुलाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के ए.टी.एम. के रूप में काम

भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ सरकार पर यह आरोप लगाते हुए सरकार को 2,161 करोड़ रूपए के शराब घोटाले में शामिल बताया।

कर रही है, इस राज्य ने 2019-23 के दौरान, 2,161 करोड़ रूपए के शराब-घोटाले के जरिये पैसा बनाया है। प्रसाद ने यह बात बुधवार को अदालत में दायर की गई 1300 पृष्ठों की एक याचिका के हवाले से कही।

उन्होंने कहा कि शराब की सभी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)